(ख) ये संस्थान इन राज्यों में कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अधीन महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिये क्रमश: महाराष्ट्र और गुजरात ने 1993–94 के दौरान 116.30 लाख रु० और वर्ष 1994–95 के लिये 181.30 लाख रु० और 37.97 लाख रु० उपलब्ध कराये हैं। परियोजना स्कीमों पर 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । विश्व बैंक परियोजना स्कीमों के विभिन्न घटकों पर कुल व्यय के कुछ प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार को करता है। इस मामले में राज्य विश्व बैंक से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त न करके केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करते हैं।

(ख) महाराष्ट्र में से ये संस्थान (i) पुणे (ii) थाने (iii) जलगांव (iv) अकोला (v) चन्दर पुर (vi) लातूर (vii) बीड (viii) रत्नागिरी (ix) भंडारा में संस्थापना हेतु प्रस्तावित है ।

गुजरात में ये संस्थान (i) उत्तर सांदा (ii) भावनगर (iii) बिल्लीमोरा (iv) विसनगर में संस्थापना हेतु प्रस्तावित है ।

Powerloom units under Labour Laws

3704. SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whteher representations has been received requesting Government to take necessary steps to bring the Powerloom units in the country under the purview of labour and factory laws, to protect the interests of the workers; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) Information is being collected.

Disparity in minimum wages

3705. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how does the minimum wages of Delhi compare with other States;

(b) the steps taken by the other State Governments to similarly revise the minimum wages to check the exploitation of the workers; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) A Statement indicating the minimum rates of wages for the lowest paid unskilled workers, in different States and Union Territory Administrations is annexed. (*See* below)

(b) and (c) The Minimum Wages Act, 1948 provides for the revision of minimum wages in a period not exceeding 5 years. The State Governments have been revising the minimum wages from time to time as per the provisions of the Act.